

Sono-1876
File No. 43015/15/2015-PRW-F
Block! Expansion of Tansi UG Mine
Sect - II
Cont - UCL

जिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY



सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 4—सितम्बर 10, 2016, शनिवार/भाद्र 13—भाद्र 19, 1938
No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 4—SEPTEMBER 10, 2016, SATURDAY/BHADRA 13—BHADRA 19, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

का.आ. 1870.—केन्द्र सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य सरकार विधायी विभाग, सचिवालय, गांधीनगर को दिनांक 22 मई, 2015 की अधिसूचना सं. जीके/14/2015/एफसीआर/102014/05/ई द्वारा दी गई सहमति से एतद्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 42) के अधीन दंडनीय सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर द्वारा दर्ज किए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले सं. 0292012 एस 0002 के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त गुजरात राज्य पर करती है।

[फा. सं. 228/71/2014-एवीडी-II]

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

कोल इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(एक महारत्न कंपनी)

एन.एल. बंगला : एन. 2, स्कोप मिनार

लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर,

लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

फोन : 91-11-22017481/485/454

फैक्स : 91-11-22010468 / 22454798

ई-मेल : coalindiadelhi@gmail.com



COAL INDIA LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(A Maharatna Company)

5th Floor, Core 1 & 2, Floor, Scope Minar,

Laxmi Nagar District Centre,

Laxmi Nagar, Delhi-110092

Phone 91-11-22017481/485/454/502

Fax 91-11-22010468 / 22454798

E-mail : coalindiadelhi@gmail.com

दिनांक 07-10-16

सीआईएल:डीएलआई.एलए:अधिसूचना:2016-17-206

सेवा में,
महा प्रबंधक (भूमि एवं राजस्व)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स
नागपुर - 440001
महोदय, (महाराष्ट्र)



विषय: भारत का राजपत्र अधिसूचना की प्रति- भूमि अर्जन
राजपत्र अधिसूचना की प्रति संलग्न है, जिसका विवरण नीचे दिए गए हैं -

विवरण	जारी तिथि	का. आ.	ब्लॉक	धारा
भाग-11-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) 10-09-16	1876	तानसी मीठाहा खान विस्तार	11	✓
भाग-11-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) 04-10-16	3144(अ)	मुंगोली-निगुड़ा विस्तार गहन विवृत (शेष भूमि) कपी क्षेत्र	4	

कृपया रसीद स्वीकार करें

धन्यवाद

भवदीय

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

डी. प्रो. लाल

3 निल गा. भूमि एवं राजस्व हेतु

डी. प्रो. लाल

डी. प्रो. लाल

डी. प्रो. लाल

92/90/2016

मुख्य प्रबंधक (कार्मिक)

07-10-16

2. In the said notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule

Magadh Expansion Project

District-Latehar, Jharkhand

(Plan bearing number REV/10 /2016, dated the 26th July, 2016)

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area(in acres)	Area in (hectares)	Remarks
1.	Chetar	Balumath	59	Latehar	37.06	15.00	Part
2.	Seregara	Balumath	60	Latehar	79.07	32.00	Part
3.	Bukru	Balumath	64	Latehar	7.41	3.00	Part
4.	Charra	Balumath	54	Latehar	3.81	1.54	Part
Total:					127.35	51.54	
Total area : 127.35 acres(approximately) or 51.54 hectares (approximately)							

Boundary Description of Magadh Expansion Project:

- A-B-C-D - Line Starts from point 'A' and passes through village Bukru, Seregara, Chetar and meets at point 'D'.
- D-E-F-A - Line passes through village chetar, Charra, Seregara, Bukru and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/2/2016-PRIW-I]

SUJEET KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal notification S.O. 591(E), dated the 22nd February, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th February, 2016.

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

का.आ.1876.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 21 मार्च, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 1170(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार उक्त भूमि में या उस पर के खनन अधिकार तारीख 21 मार्च, 2016 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-

1. सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
2. शर्त (1) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और किसी ऐसे अधिकरण और अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के खनन अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपीलों आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे।
3. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो।
4. सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त भूमि और भूमि में या उसके उपर इस प्रकार निहित अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
5. सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के खनन अधिकार के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/15/2015—पीआरआईडब्ल्यू-1]

सुजीत कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2016

S.O. 1876.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S. O. 1170(E), dated the 18th March, 2016, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st March, 2016, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the mining rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, Nagpur (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby directs that the mining rights in or over the said land so vested shall with effect from the 21st March, 2016, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely :-

1. The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
2. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government, by the Government Company under conditions (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the mining rights, in or over the said lands, so vesting, shall also be borne by the Government Company;
3. The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
4. The Government Company shall have no power to transfer the lands to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

5. The Government Company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for mining rights of particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/15/2015-PRIW-I]

SUJEET KUMAR, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

का.आ. 1877.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डालमिया मैग्नेसाइट कॉर्पोरेशन के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, चैन्नई के पंचाट (संदर्भ सं. 83, 85/2012) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 29.08.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43011/37/2012-आईआर (एम),

सं. एल-43011/36/2012-आईआर (एम)]

समीर कुमार दास, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 31st August, 2016

S.O. 1877.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 83, 85/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dalmia Magnesite Corporation and their workman, which was received by the Central Government on 29.08.2016.

[No. L-43011/37/2012-IR (M),

No. L-43011/36/2012-IR (M)]

SAMIR KUMAR DAS, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT,
CHENNAIThursday, the 30th June, 2016

Present : K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 83 & 85 of 2012

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Dalmia Magnesite Corporation and their workman)

BETWEEN :

ID 83/2012

The General Secretary
Magnesite National Labour Union
Vazhapadi K. Ramamoorthy Illam
52, Dr. Subbarayan Road
Salem-626001

: 1st Party/Petitioner Union

AND